SSHAP | Social Science in Humanitarian Action Platform www.socialscienceinaction.org

इन-फोकस (एक झलक):

कोविड-19, भारत में अनिश्चितता, वल्नरबिलीटी और रिकवरी

भारत में असमानता, असुरक्षा और कोविड-19 महामारी के परस्पर मिले जुले प्रभाव ने गरीब और सुभैद्य समूहों (vulnerable communities) के लिए अनिश्चितताएं बढ़ा दी हैं। इससे असुरक्षा की भावना, लांछन (stigma) लगा और आजीविका का बहुत अधिक नुकसान हुआ है। एक सख्त सरकारी लॉकडाउन ने किसानों और शहरी अनौपचारिक अनियमित कामगारों की आय को समाप्त कर दिया। भारत के शहरों से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। देश में लॉकडाउन प्रतिबंध, लू, बाढ़ और चक्रवातों के साथ शुरू हुआ था जिससे आपदा प्रबंधन और राहत कार्यो में भी बाधा उत्पन्न हुई। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने, असहमति को दबाने और संवैधानिक दायित्वों या मूल्यों को कमजोर करने के लिए इस महामारी का राजनीतिकरण भी हुआ है।

सारांश

- भारत में, कोविड-19 महामारी ने मोजुदा अनिश्चितताओं को बढ़ाया है। यह अनिश्चितताओं खाद्य और कृषि, जल और स्वच्छता, रोजगार, ऋणग्रस्तता (indebtedness), स्वास्थ्य, जलवायु और आपदा प्रबन्धन से जुडी हुई है।
- कोविड-19 के प्रभावों को वर्ग, जाति, लिंग, नस्ल, धर्म और सामूहिक सीमाओं में विभेदित (differentiated) किया जाता है। यह अनिश्चितताओं, सुभैद्य और अल्पसंख्यक समूहों (vulnerable and minority communities) द्वारा अधिक तीव्रता से अनुभव किया गया है- जो मुख्यधारा के विकास के रास्ते में काफी हद तक 'अदृश्य' बने हुए हैं।
- भारत का लॉकडाउन तेज गर्मी और मानसून की अवधि के दौरान आरंभ हुआ, तभी चक्रवात, बाढ़ और लू ने भी कमजोर वर्ग के लोगों और समुदायों को बहुत प्रभावित किया। जटिल अनिश्चितताओं के कारण होने वाली कठिनाइयों से सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक समूहों को बहुत जोखिम वाली तैयारियों पर एक साथ काम करने की आवश्यकता दिखाई देती है।
- कोविड-19 महामारी के प्रत्युत्तर में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों उपायों की आवश्यकता है। जबकि अल्पकालिक उपायों को तत्काल राहत और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, दीर्घकालिक उपायों को भोजन, पानी, स्वास्थ्य, नौकरियां और आश्रय/आवास जैसी बुनियादी जरूरतों के अधिकार की गारंटी देनी चाहिए।
- भारत के क्षेत्रफल और विविधता का मतलब है कि राष्ट्रीय रणनीतियां स्थानीय स्तर पर हमेशा काम नहीं कर सकती हैं। इसके बजाय, राज्य एजेंसियों को एक बॉटम-अप, समुदाय आधारित मॉडल अपनाना चाहिए, जिससे प्रभावित क्षेत्रों के संगठनों को अंतर्निहित सामाजिक और सांस्कृतिक असमानताओं को संबोधित करते हुए स्थानीय संदर्भ में राहत उपायों को अनुकूल बनाने की कोशिश की जा सके।

Contact: j.pickard2@ids.ac.uk

- कोविड-19 और भविष्य की महामारियों का सामना करते हुए, हाशिए पर पड़े समूहों की बातों और अनुभवों को नागरिकों के सामाजिक संगठनों के लिए एक मजबूत भूमिका के साथ सरकार की तैयारी रणनीतियों (preparedness)को आकार देना चाहिए।
- ग्रामीण भारत में अनौपचारिक प्रवासियों की वापसी ने ग्रामीण पुनरुद्धार (revival) के अवसर प्रदान किये है। सरकारी निवेश और रोजगार गारंटी कार्यक्रमों को फिर से लक्षित करना चाहिए, जिससे सामुदायिक संपत्ति की बढ़ौती हौ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कृषि पर निर्भरता कम हो सके।
- सुधार की योजनाओं (recovery plans) में मौजूदा असमानताओं और भेदभावपूर्ण प्रथाओं, मानवाधिकारों को सार्वभौमिक बनाने और सार्वजनिक वस्तुओं तक पहुंच की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए।
- महामारी के दौरान सरकारी राहत और सामाजिक सुरक्षा उपायों की विफलताओं में एक सार्वभौमिक, पोर्टेबल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) सहित सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को दर्शाया है। इस नये तरीके के PDS में अधिवास (domicile) की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और भोजन, पानी और आवास/आश्रय के लिए सार्वभौमिक हकदारी होनी चाहिए।
- कोविड-19 का उपयोग बढ़ी हुई सरकारी निगरानी को वैध बनाने के लिए किया गया। यह लॉकडाउन और महामारी संबंधित असहमति को दबाने, लोकतांत्रिक मूल्यों और मानव अधिकारों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि बोलने और असहमति के अधिकार के संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखा जाए।

भारत में कोविड-19

भारत में कोविड-19 का पहला मामला दक्षिण भारतीय राज्य केरल में 30 जनवरी, 2020 को सामने आया था। 25 मार्च, 2020 को घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने 130 करोड़ (1.3 billion) आबादी को अपने घरों तक सीमित कर दिया। प्रारंभिक लॉकडाउन उपायों में आर्थिक गतिविधियों को स्थगित करते समय शारीरिक दूरी बनाए रखना और एकांतवास का कड़ाई से पालन करना आवश्यक था। यहां सरकार सबसे अधिक प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने में विफल रही।[1]

यह समझना महत्वपूर्ण है कि अनिश्चित, सुभेद्य (vulnerable) और अल्पसंख्यक समूहों द्वारा इन प्रभावों का अनुभव कैसा किया गया है। इस महामारी ने जाति, वर्ग, धर्म, लिंग और शिक्षा की मौजूदा संरचनात्मक असमानताओं को बरकरार रखा और बढ़ाया है। कोविड-19 और संबंधित कमजोरियां भारत के सभी नागरिकों के लिए बुनियादी आश्रय/आवास, भोजन, पानी, और स्वच्छता सहित सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है।

जटिल अनिश्चितताएं

अनौपचारिक शहरी आजीविका

लॉकडाउन में इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय शहर अनौपचारिक, अनियमित गतिविधि पर कितना निर्भर करते हैं।[2] कई आंकड़ो के अनुसार, भारत की जी.डी.पी. में आधा योगदान अनियमित श्रमिकों का होता हैं। लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियों के निलंबन से ईन अनियमित श्रमिकों की आय को काभी क्षति पहोंची। लॉकडाउन के प्रभावों को प्रवासी

श्रमिकों[3,4], सफाई कर्मियों,[5] और यौनकर्मियों[6] सहित अनिश्चित रोजगार में लगे हुए लोगों द्वारा विशेष रूप से महसूस किया गया। लेकिन औपचारिक अर्थव्यवस्था में नियोजित लोगों में से भी, आधे से अधिक को लॉकडाउन के दौरान कम या निलंबित वेतन प्राप्त हुआ।[7]

ग्रामीण आजीविका

ग्रामीण भारत में, लॉकडाउन सर्दी की फसल की कटाई के साथ लागू किया गया था। इस बजह से किसानों को उपज के भंडारण, वितरण और निर्यात में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ ने खराब होने वाली वस्तुओं या पशु चारे के लिए फसलों का इस्तेमाल किया या उसे फेंक दिया। खेतों में फसल सड़ न जाए इसके लिए दूसरी जगह किराए पर ली ताकि उपज को वहां रखा जा सके।[8] कई लोगों ने अपने जीवन यापन हेतु स्वयं के उत्पाद का उपयोग किया और खाद्य आपूर्ति पर लॉकडाउन के दबाव को कम किया।[9]

लॉकडाउन ने मानसून से पहले ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई में भी बाधा डाली। लॉकडाउन प्रतिबंधों के साथ सीमित श्रम और कृषि आदानों से और अधिक बढ़ गया।

जलवायु, प्राकृतिक आपदाए, और कोविड-19

इस महामारी का प्रकोप भारत में कई प्राकृतिक आपदाओं जैसे अम्फान चक्रवात (पश्चिम बंगाल और उड़ीसा)[10] और निसर्ग चक्रवात (महाराष्ट्र)[11], बाढ़[12,13], सूखा और लू के साथ पड़ा। जटिल अनिश्चितताओं ने कोविड-19 और प्राकृतिक आपदाओं के लिए तत्काल प्रतिक्रियाओं को बाधित किया, और साथ ही इस महामारी का सामाजिक और पारिस्थितिक प्रणालियों (social and ecological systems) पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है।[14,15] भविष्य की ओर देखते हुए भारत की कोविड-19 की प्रतिक्रिया से आपदा और जलवायु परिवर्तन प्रबन्धन के कई सबक लिए जा सकते है।

कमजोर समुदाय

कोविड-19 के आड़ में कमजोर समुदायों को कलंकित करने की कोशिश की गई। लॉकडाउन का प्रभाव पहले से ही कमजोर वर्गों द्वारा अधिक महसूस किया गया था, जिनमें से कई को वायरस के परिणामस्वरूप कलंकित किया गया। सिकुड़ती अर्थव्यवस्था में, सुभेद्य समूहों (vulnerable communities) के लिए जीविका, स्वास्थ्य और राहत का उपयोग करना कठिन साबित हुआ। तेज आर्थिक गिरावट को देखते हुए विशेषज्ञों को डर है कि वर्तमान में गरीबी रेखा से ठीक ऊपर 10 करोड़ (100 million) लोग अब इससे नीचे पहुँच जाएंगे।[16]

सीमित सरकारी राहत

कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए, भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहेने वाले परिवारों के लिए अनाज, दाल और मुफ्त गैस सिलेंडर सहित तरह-तरह कि राहत प्रदान करी। प्रधान मंत्री जन-धन योजना वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में नामांकित महिलाओं के खातों में भुगतान जमा किया गया। विधवाओं, पेंशनभोगियों और विकलांग लोगों को एकमुश्त राशि और पेंशन पर अग्रिम प्राप्त हुआ।

हालांकि, कई लोगों को इन हकों तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ लाभ केवल राशन कार्ड, आधार आईडी या सक्रिय बैंक खातों वाले लोगों को ही मिले। जो परिवार इन लाभों से वंचित रह गये उनको या तो अपनी बचत के पैसे का इस्तमाल करना पड़ा या उधार लेना पड़ा। इन चुनौतियों का जवाब देते हुए सरकार को लाभ तक पहुंच में सुधार करना चाहिए। बढ़े हुए सुरक्षा उपाय और अधिक स्टाफ के साथ, राजस्थान और तमिलनाडु में ग्रामीण नौकरियों की गारंटी योजनाओं में उपयोग किए जाने वाले नकद-इन-हैंड भुगतान, एक समाधान पेश कर सकते हैं।[17]

अनौपचारिक(अनियमित) कामगारों की वापसी

शहरी आजीविका के समाप्त होने की वजह से, अनुमानित 2.2-2.5 करोड़ (22-25 million) अंतर-राज्यीय प्रवासियों ने मार्च और अप्रैल[18] में भारत के शहरों को छोड़ दिया, जिससे वह अपने राज्यों और मूल गांवों में वापस आ गए। लॉकडाउन के प्रभावों के बारे में बहुत कम विचार विमर्श किया गया। इसलिये भारत सरकार इस जन प्रवास के लिए तैयार नहीं थी।[19] प्रवासी हेल्पलाइनों ने 1,00,000 से अधिक संकट कॉलों की सूचना दी और राज्यों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा 38,000 राहत शिविर स्थापित किए गए।

श्रम और रोजगार मंत्रालय को कस्बों, शहरों और राज्यों में प्रवासियों के प्रवाह को ट्रैक करना चाहिए और अंतर-राज्यीय पारवहन के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। राज्य सरकारों को अंतर्राज्यीय प्रवासी अधिनियम (1979) के कार्यान्वयन को मजबूत करना चाहिए, जो कमजोर प्रवासियों को सुरक्षा प्रदान करता है। इन कदमों से सरकार को देश के विभिन्न भागों में श्रम संबंधी अवसरों का समन्वय करने में मदद मिल सकती है।

अल्पसंख्यक समूह के प्रति कलंक(धब्बा)

भारत के भीतर, महामारी ने सामाजिक संबंधों को संकुचित किया है। दलित अपनी सामाजिक स्थिति के कारण महामारी में सबसे अधिक जोखिम में रहें।[20] इस्लामी मिशनरी संप्रदाय तबलीघी जमात के सदस्यों के बीच एक शुरुआती प्रकोप को मीडिया का व्यापक ध्यान मिला। वायरस के फैलाव[21,22] में इन्हे एक प्रमुख कारक के रूप में देखा गया। मुसलमानों को कलंकित करने की वजह से आत्महत्याएं, मस्जिदों और ट्रक ड्राइवरों पर हमले बढ़ें, और मुस्लिम स्वामित्व वाले व्यवसायों का बहिष्कार हुआ।[23,24 ,25] लौटने वाले प्रवासी कामगारों को भी वायरस के संभावित वाहक के रूप में चिन्हित किया गया था। उत्तर प्रदेश और बिहार में एहतियातन 14 दिन के संगरोध के बाद भी दिल्ली और अन्य शहरों से लौट रहे मजदूरों को 'सामाजिक बहिष्कार' का शिकार होना पड़ा।[26,27]

भारत सरकार की सुरक्षा और राहत लाभ पहोंचाने की सीमाओ को देखतें हुए, कई अंतरराष्ट्रीय ह्युमन राइट्स संगठनों (human rights organisations) का सुरक्षा, राहत, हानि मुआवजा, भेदभाव की निगरानी (monitoring discrimination) एवं आर्थिक प्रोत्साहन (economic stimulus) में एक नई भूमिका सामने आयी है।

महिलाओं पर प्रभाव

अक्सर गैर मान्यता प्राप्त या अनौपचारिक अनियमित असंगठित क्षेत्रों में नियोजित, श्रम बल से महिलाओं की अनुपस्थिति सरकारी आंकड़ों में कम देखने की संभावना है।[28] हालांकि महिलाओं की तुलना में पुरुषों ने लॉकडाउन के परिणाम फलस्वरूप जीविका कि हानि को महसूस किया, एसा भी देखा गया कि लॉकडाउन से पहले काम करती हुइ महिलाओं का लॉकडाउन के

बाद काम करने कि संभावना 20% से कम हो गई।[29] लॉकडाउन ने उन ग्रामीण महिलाओं के लिए आय को भी क्षीण कर दिया जो गर्मी की अवधि में कृषक या दिहाडी मजदूर के रूप में काम पाते हैं।[30]

कोविड-19 प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए अग्रिम पंक्ति और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को डायवर्ट करने के साथ ही महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी महिला और बाल विकास मंत्रालय पर है। महिलाओं की आजीविका के महत्व को मान्यता दी जानी चाहिए और सहायता और वित्तीय सहायता के लिए भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

रिकवरी और परिवर्तनकारी रास्ते

महामारी से 'रिकवरी' असमान साबित हुई है, जिससे कुछ समूहों को लाभ हुआ है, जबकि मोजुदा असमानताओं को बल मिला है। विभाजित (siloed) सरकारी ऑपरेशन्स को चुस्त और अनुकूली प्रणाली (adaptive systems) को रास्ता देने की जरूरत है। यह महत्वपूर्ण है कि भारत के राज्यों और जिलों को भोजन और आवश्यक सेवाओं के वितरण के लिए लचीला, समावेशी और विकेंद्रीकृत रणनीतियां विकसित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, और परीक्षण, ट्रेसिंग, और उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियां भी प्रदान की जाये।

बॉटम-अप और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से ग्रामीण पुनरुद्धार

लॉकडाउन के बाद, ग्रामीण मांग को बढ़े हुए सरकारी राहत खर्च, और समय से पहले हुए गर्मियों कि बुवाई से उत्साह मिला। हालांकि गांवों में तैयार काम की कमी ने पहले ही शहरों में वापसी को शह दी है, लेकिन लंबी दूरी के पलायन को अब जोखिम भरा माना जा रहा है, एक धारणा है कि राज्य में पलायन में वृद्धि हो सकती है।[31,32]

तथापि, गैर-कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण बुनियादी ढांचे की मरम्मत और अद्यतन करने के लिए इस श्रम पूल का दोहन करने के अवसर हैं।[33] वस्तुओं और सेवाओं के लिए भारत की घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है, यहां तक कि लगातार लॉकडाउन से उत्पादकों और बिचौलियों के बीच विश्वास कमजोर हुआ है। निवेश से ग्रामीण उत्पादकों को ऋण और आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराते हुए व्यापार संबंधों को बहाल करने में मदद मिल सकती है।

समावेशी कल्याण नीतियां

मनरेगा और रोजगार गारंटी कार्यक्रम

कोविड-19 महामारी से उबर ने का एक अवसर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने प्रदान किया है। मनरेगा का इस्तमाल करके सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा सकता है जिससे लोगों को गरीबी रेखा से उपर रखने में मदद मिलेंगी।[34] मनरेगा सरकार के लिए दीर्घकालिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम कल्याणकारी कार्यक्रम बनाने की नींव प्रस्तुत करता है। स्थानीय मजदूरों, विशेष रूप से वो जो भूमिहीन है, उनको कृषि के कार्यो, फेस मास्क और सैनिटाइजर का निर्माण, या स्थानीय बैंकिंग और भुगतान अवसंरचनाओं में कार्यरत किया जा सकता हैं।[35]

सामाजिक सुरक्षा कि मजबूती

मौजूदा सरकारी सुरक्षा जाल काफी हद तक भारत के ग्रामीण गरीबों पर केंद्रित है, जिससे शहरी समूह विशेष रूप से असुरक्षित हैं। प्रवासी पलायन ने निश्चित निवास और गैर-पोर्टेबल हकदारियों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा आर्किटेक्चर (social

protection architectures) की कमजोरियों का खुलासा हुआ। यदि सार्वभौमिक हकदारियों (universal entitlements) का प्रयोग किया गया होता तो प्रवासी मजदूरो को लॉकडाउन के समय जीविका का नुकसान न जेलना पड़ता और शहेरों से पलायन भी न करना पड़ता।[36] इस तरह के सुरक्षा तंत्र के बिना, कोविड-19 के अतिरिक्त दबाव, इन समूहों के सदस्यों को ऋण जाल में धकेलने की संभावना प्रस्तुत करते है। इससे नागरिकों को भोजन, पानी और आश्रय की अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य, शिक्षा और बैंकिंग बुनियादी ढांचे के पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने वाले उपायों से बचा जा सकता है।[37]

जवाबदेही और विश्वास में सुधार

लॉकडाउन के दौरान सरकार ने नागरिक समाजिक संगठनों के साथ सहयोग करने की क्षमता और इच्छा की कमी दिखाई। लचीलापन को बढ़ावा देने और प्रभावी ढंग से भविष्य में आने वाले चुनौतियों के लिए प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने के लिए, शासन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, और नागरिक समाज समूहों, मानवीय और विकास संगठनों के साथ बातचीत के लिए खुला होना चाहिए।

सरकार की तैयारी प्रतिक्रिया(preparedness) को आकार देने के लिए सुभेद्य समूहों (vulnerable communities), नागरिक समाज की आवाजों और अनुभवों को शामिल किए जाने की जरूरत है। एक बॉटम-अप, समुदाय आधारित मॉडल एक तेज और अधिक मजबूत रिकवरी को रेखांकित कर सकता है। एसा करने से उन संगठनों और प्राधिकरणों को महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में, सुभेद्य वर्गों कि जरुरतों के हिसाब से राहत उपायों का रेखांकन करने का अवसर मिलेंगा।

संदर्भ

[1] Ray, D., & Subramanian, S. (2020). *India's Lockdown: An Interim Report* (NBER Working Paper No. 27282; p. 70). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w27282

[2] Arvind, J., & Govindarajan, V. (2020, April 10). *Coronavirus: India's lockdown has led to chaos because the government misunderstood how cities work*. Scroll.in. https://scroll.in/article/958140/coronavirus-indias-lockdown-has-led-to-chaos-because-the-government-misunderstood-how-cities-work

[3] Stranded Workers Action Network. (2020). *32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India* (p. 46). Stranded Workers Action Network. https://covid19socialsecurity.files.wordpress.com/2020/05/32-days-and-counting_swan.pdf

[4] Stranded Workers Action Network. (2020, June 5). *To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home* (p. 78). Stranded Workers Action Network. http://strandedworkers.in/wp-content/uploads/2020/06/SWAN-Report05062020-1.pdf

[5] Singh, K., & Somani, P. (2020, September). *Health, Safety and Social Security Challenges of Sanitation Workers during the COVID-19 Pandemic in India* (p. 28). Urban Management Centre and WaterAid India. https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/health-safety-and-social-security-challenges-of-sanitation-workers-during-the-covid-19-pandemic-in-india.pdf

[6] Tripathi, P. (2020, August 1). Social Distancing and Sex Workers in India. *Economic & Political Weekly* 55 (31), 21-23. https://www.epw.in/journal/2020/31/commentary/social-distancing-and-sex-workers-india.html

[7] Lahoti, R., Basole, A., Abraham, R., Kesar, S., & Nath, P. (2020, May 27). *Hunger Grows as India's Lockdown Kills Jobs*. The India Forum. https://www.theindiaforum.in/article/hunger-grows-india-s-lockdown-kills-jobs

[8] Jadhav, R., Bhardwaj, M., & Thukral, N. (2020, April 1). *Coronavirus lockdown leaves no-one to harvest India's crops*. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-india-harvests-idUSKBN21J4Z3

[9] Kesar, S., Abraham, R., Lahoti, R., Nath, P., & Basole, A. (2020). *Pandemic, informality, and vulnerability: Impact of COVID-19 on livelihoods in India* (CSE Working Paper No. 2020–01). Centre for Sustainable Employment, Azim Premji University. https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/wp-content/uploads/2020/06/Kesar_et_al_Pandemic_Informality_Vulnerability.pdf

[10] Das, M. (2020, May 19). With PPE kits and masks, Mamata govt gets ready to face "super cyclone" Amphan. *ThePrint*. https://theprint.in/india/with-ppe-kits-and-masks-mamata-govt-gets-ready-to-face-super-cyclone-amphan/425140/

[11] Johari, A. (2020, June 2). *As Cyclone Nisarga approaches Mumbai, areas hit by Covid-19 are bracing for the worst*. Scroll.in. https://scroll.in/article/963613/as-cyclone-nisarga-approaches-mumbai-areas-hit-by-covid-19-are-bracing-for-the-worst

[12] Chakrabarti, A., & Longkumer, Y. (2020, June 26). Covid hit first, then floods—How Assam's Goalpara handled both with "no time to prepare." *ThePrint*. https://theprint.in/india/covid-hit-first-then-floods-how-assams-goalpara-handled-both-with-no-time-to-prepare/448367/

[13] Prasad, E., & Choudhury, N. (2020, May 28). *Is North Bihar prepared for the overlapping challenge of COVID-19 and the annual floods?* GaonConnection. https://en.gaonconnection.com/is-north-bihar-prepared-for-the-overlapping-challenge-of-covid-19-and-the-annual-floods/

[14] Phillips, C. A., Caldas, A., Cleetus, R., Dahl, K. A., Declet-Barreto, J., Licker, R., Merner, L. D., Ortiz-Partida, J. P., Phelan, A. L., Spanger-Siegfried, E., Talati, S., Trisos, C. H., & Carlson, C. J. (2020). Compound climate risks in the COVID-19 pandemic. *Nature Climate Change*, *10*(7), 586–588. https://doi.org/10.1038/s41558-020-0804-2

[15] Srivastava, S., Mehta, L., & Bose, S. (2020, June 25). *A "natural disaster" on top of a pandemic – preparedness in the face of cascading uncertainties*. Institute of Development Studies. https://www.ids.ac.uk/opinions/a-natural-disaster-on-top-of-a-pandemic-preparedness-in-the-face-of-cascading-uncertainties/

[16] Perrigo, B., & Thirani Bagri, N. (2020, August 19). *How a Deepening Coronavirus Crisis Is Reshaping India*. Time. https://time.com/5880585/india-coronavirus-impact/

[17] Khera, R. (2020, May 25). *Why cash can save the rural jobs scheme*. Livemint. https://www.livemint.com/news/india/why-cash-can-save-the-rural-jobs-scheme-11590421706597.html

[18] Chishti, S. (2020, June 8). Explained: How many migrant workers displaced? A range of estimates. *The Indian Express*. https://indianexpress.com/article/explained/coronavirus-how-many-migrant-workers-displaced-a-range-of-estimates-6447840/

[19] Baxi, U. (2020, June 11). *Exodus Constitutionalism*. The India Forum. https://www.theindiaforum.in/article/exodus-constitutionalism

[20] Ganguly, S. (2020, June 2). *India's coronavirus pandemic shines a light on the curse of caste*. The Conversation. http://theconversation.com/indias-coronavirus-pandemic-shines-a-light-on-the-curse-of-caste-139550

[21] Ali, A. (2020, April 1). *Coronavirus was a test of secular nationalism. Then Tablighi Jamaat became the scapegoat*. ThePrint. https://theprint.in/opinion/coronavirus-test-of-secular-nationalism-tablighi-jamaat-became-scapegoat/392764/

[22] Razzack, A., & Alvi, M., F. (2020, July 21). *Communalism and COVID-19 have changed the classroom for Indian Muslim children*. The Wire. https://thewire.in/education/covid-19-communalism-caa-anti-muslim-school-reopen

[23] Mander, H. (2020, April 13). *The Coronavirus Has Morphed Into an Anti-Muslim Virus*. The Wire. https://thewire.in/communalism/coronavirus-anti-muslim-propaganda-india

[24] Bera, S. (2020, May 7). *Money for nothing, pumpkins for free*. Livemint. https://www.livemint.com/industry/agriculture/money-for-nothing-pumpkins-for-free-11588863832315.html

[25] Vardaraj, A., & Prateek, G. (2020, April 27). *The challenges faced by rural India during the lockdown*. Asiaville. https://www.asiavillenews.com/article/the-challenges-faced-by-rural-india-during-the-lockdown-41594

[26] Mishra, D. (2020, March 31). 'No one wants to go near them'—Returning migrant workers in Bihar face social boycott. *ThePrint*. https://theprint.in/india/no-one-wants-to-go-near-them-returning-migrant-workers-in-bihar-face-social-boycott/392081/

[27] Kumar, C., & Mohanty, D. (2020, May 10). *Migrant workers battle stigma, bias back home*. Hindustan Times. https://www.hindustantimes.com/india-news/migrant-workers-battle-stigma-bias-back-home/story-0uuRSEZfoickVOrPU2agGL.html

[28] Priyadarshini, A., & Chaudhury, S. (2020). The Return of Bihari Migrants after the COVID-19 Lockdown. In R. Samaddar (Ed.), *Borders of an Epidemic: COVID-19 and Migrant Workers* (pp. 66–75). Mahanirban Calcutta Research Group. http://www.mcrg.ac.in/RLS_Migration_2020/COVID-19.pdf

[29] Deshpande, A. (2020). *The Covid-19 Pandemic and Lockdown: First Effects on Gender Gaps in Employment and Domestic Work in India* (No. 30; Discussion Paper Series in Economics, p. 21). Ashoka University. ftp://52.172.205.73/ash/wpaper/paper30.pdf

[30] Kulkarni, S., Harshe, P., Satpute, S., & Bhat, S. (2020). *Unlocking the Crisis: Understanding impacts of COVID-19 and subsequent lockdown on single women farmers of Maharashtra* (p. 35). MAKAM. https://aidindia.org/wp-content/uploads/2020/06/Unlocking-the-crisis-english-final-report210620.pdf

[31] Deshingkar, P. (2020, May 18). *Why India's migrants deserve a better deal*. Livemint. https://www.livemint.com/news/india/why-india-s-migrants-deserve-a-better-deal-11589818749274.html

[32] Rajan, I. (2020, May 19). *Interview: 'Migrant labourers now have an opportunity to punish their employers'* (H. Pullanoor, Interviewer) [Quartz India interview]. https://qz.com/india/1858209/covid-19-lockdown-exposes-indias-looming-migrant-refugee-crisis/

[33] SV, P., & Reddy, S. A. (2020, May 21). *Does Karnataka's rural economy have space for returning migrant workers?* [Text]. Scroll.in. https://scroll.in/article/961973/does-karnatakas-rural-economy-have-space-for-returning-migrant-workers

[34] Narayanan, S. (2020, March 17). *The Continuing Relevance of MGNREGA*. The India Forum. https://www.theindiaforum.in/article/continuing-relevance-mgnrega

[35] Seshan, K., & Biswas, A. (2020, May 5). *Transforming lives in the Covid-19 context: MGNREGS and its potential*. India Water Portal. https://www.indiawaterportal.org/articles/transforming-lives-covid-19-context-mgnregs-and-its-potential

[36] Muralidharan, K. (2020, June 10). *A post-Covid-19 social protection architecture for India*. Hindustan Times. https://www.hindustantimes.com/analysis/a-post-covid-19-social-protection-architecture-for-india/story-BCt1POzFojnKloCkHTsv9H.html

[37] Bhatt, E. R. (2020, May 6). How do we build a society less susceptible to debt, disease, devastation? *The Indian Express*. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/india-covid-19-pandemic-healthcare-banki-essential-supply-system-ela-r-bhatt-6395643/

अतिरिक्त संसाधन

टेपेस्ट्री-प्रैक्सिस के रूप में परिवर्तन: सीमांत वातावरण में स्थिरता के लिए सामाजिक रूप से बस और ट्रांसडिसिप्लिनरी रास्तों की खोज। स्टेप्स सेंटर, ससेक्स विश्वविद्यालय। TAPESTRY—Transformation as Praxis: Exploring Socially Just and Transdisciplinary Pathways to Sustainability in Marginal Environments. STEPS Centre, University of Sussex. https://steps-centre.org/project/tapestry/

भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया COVID-19 (आईएसआरसी)। Indian Scientists' Response to COVID-19 (ISRC). https://indscicov.in/

सहयोग/COVID एक्शन सपोर्ट टीम (CoAST) भारत। इंडिया ऑब्जर्वेटरी। Collaboration/COVID Action Support Team (CoAST) India. India Observatory. https://dp.observatory.org.in/content/migration-route-covid-19

सीपीआर थॉटस्पेस। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली, भारत। CPR Thought Space. Centre for Policy Research, New Delhi, India. https://casi.sas.upenn.edu/iit/covid-19

कोरोना टाइम्स के जवाब में। विकलपसंसगम, भारत। In Response to Corona Times. Vikalp Sangam, India. https://vscoronatimes.blogspot.com/

लॉकडाउन और उससे आगे के दौरान बातचीत। सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, इंडिया। Conversations during lockdown & beyond. Centre for Financial Accountability, India. https://www.cenfa.org/webinar-solidarity-series/

स्वीकृति

हम डी. पार्थसारथी (आईआईटी-बी, भारत) का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे; सीमा कुलकर्णी (SOPPECOM और MAKAAM, भारत) ; अमिता भिड़े (TISS, भारत) ; गीर्ट डी नेवे (ससेक्स विश्वविद्यालय, ब्रिटेन) और उनकी समीक्षा और आदानों के लिए SSHAP टीम के सदस्यों।

संपर्क

यदि आपके पास संक्षिप्त, उपकरण, अतिरिक्त तकनीकी विशेषज्ञता या दूरस्थ विश्लेषण के बारे में COVID-19 की प्रतिक्रिया से संबंधित सीधा अनुरोध है, या आपको सलाहकारों के नेटवर्क के लिए विचार करना चाहिए, तो कृपया एनी लोडेन(a.lowden@ids.ac.uk)या ओलिविया तुलोच(oliviatulloch@anthrologica.com)को ईमेल करके मानवीय कार्रवाई मंच में सामाजिक विज्ञान से संपर्क करें। प्रमुख मंच संपर्क बिंदुओं में शामिल हैं: यूनिसेफ(nnaqvi@unicef.org); आईएफआरसी(ombretta.baggio@ifrc.org); और GOARN रिसर्च सोशल साइंस ग्रुप(nina.gobat@phc.ox.ac.uk).

सोशीयल सायन्स इन ह्युमेनीटेरीयन एक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, एन्थ्रोलोजीका और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के बीच एक साझेदारी है। COVID-19 के लिए मंच की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए वित्तपोषण वेलकम ट्रस्ट और एफसीडीओ द्वारा प्रदान किया गया है। व्यक्त की राय लेखकों के उन है और जरूरी विचारों या आईडीएस, एन्थ्रोलोजीका, LSHTM, वेलकम ट्रस्ट या ब्रिटेन सरकार की नीतियों को प्रतिबिंबित नहीं करते।

Suggested citation: Pickard, J., Srivastava, S., Bhatt, M. and Mehta, L. (2020) In-Focus: COVID-19, Uncertainty, Vulnerability and Recovery in India', Brighton: Social Science in Humanitarian Action (SSHAP) DOI: 10.19088/SSHAP.2021.010

सुझाए गए प्रशस्ति पत्र: पिककार्ड, जे., श्रीवास्तव, एस., भट्ट, एम. और मेहता, एल. (2020) इन-फोकस: COVID-19, अनिश्चितता, भेद्यता और भारत में वसूली', ब्राइटन: सोशीयल सायन्स इन ह्युमेनीटेरीयन एक्शन (SSHAP) DOI: 10.19088/SSHAP.2021.010

नवंबर 2020 प्रकाशित

© इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज 2020

यह क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन 4.0 इंटरनेशनल लाइसेंस (सीसी बाय) की शर्तों के तहत वितरित एक ओपन एक्सेस पेपर है, जो किसी भी माध्यम में अप्रतिबंधित उपयोग, वितरण और प्रजनन की अनुमति देता है, बशर्ते मूल लेखकों और स्रोत को श्रेय दिया जाए और किसी भी संशोधन या रूपांतरों को इंगित किया जाए। http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode